क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 279, शनिवार, 03 नवम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

अब सुप्रीम कोर्ट का नजारा कर सकेंगे पर्यटक

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं। हर शनिवार को दस से एक बजे तक सुप्रीम कोर्ट घूमा जा सकता है। लेकिन इसके लिए अनलाइन आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस संबंध में वेबसाइट में दी गई जानकारी को सार्वजनिक किया। 20 लोगों तक के समूह को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। यह भ्रमण निशुल्क होगा। आवेदन करने के बाद स्वीकृति दी जाएगी और समय निर्धारित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भव्य कोर्टरूम, जज लाइब्रेरी तथा संग्रहालय का भ्रमण किया जा सकेगा।

चिदंबरम को गिरफ्तारी से 26 तक अंतरिम राहत

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए एयरसेल मैक्सिस धन शोधन मामले में गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तथा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 26 नवंबर तक अंतरिम राहत प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी। ईडी ने इस मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ का आग्रह किया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने मामले की सुनवाई के बाद चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी।

सभी महिलाओं को ये अधिकार देने की मांग वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने दिया ये तर्क

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आयु वर्ग और धर्मों की महिलाओं को मंदिरों, मस्जिदों और 'पारसियों के अग्नि मंदिर में जाकर पूजा करने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस वी. के. राव की बैंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बैंच ने कहा कि याचिका दायर करने वाले ने यह नहीं बताया है कि याचिका में उल्लिखित कौन-कौन से मंदिर इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यहां उल्लिखित मंदिरों में से कोई भी इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हम इस पर विचार करने की इच्छा नहीं रखते हैं और याचिका खारिज की जाती है। वकील संजीव कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि महिलाओं को भी पूजा कराने के लिए संबंधित मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में क्रमश: पुजारी, इमाम और पादरी का पद मिलना चाहिए।

ईयरफोन लगाकर कार चला रहे कारोबारी ने बच्चे को कुचला, मौत

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में बुधवार को ईयरफोन लगाकर कार चला रहे एक कारोबारी ने सात साल के बच्चे को कुचल दिया। घटना के बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक बच्चे की पहचान सात वर्षीय रजत के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार चला रहे कारोबारी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी कारोबारी की पहचान गौरव (27) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सेकेंड क्लास में पढ़ने वाला रजत परिवार के साथ हर्ष विहार के गली नंबर-7 में रहता था। उसके परिवार में पिता प्रदीप कुमार, मां रेनू देवी और एक छोटा भाई शिव है।

तिरुवनंतपुरम स्थित प्रख्यात पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बुधवार को दर्शन के लिए क्रिकेटर शिखर धवन व उमेश यादव के साथ पहुंचे टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री।

हाईकोर्ट के दखल से 18 दिन बाद हरियाणा रोडवेज कर्मियों की हड़ताल खत्म, कल से फिर दौड़ेंगी बसें

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की सख्ती और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों ने 18 दिन से चली आ रही अपनी हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि शनिवार सुबह 10 बजे तक प्रदेश में रोडवेज बसों का परिचालन पुन: शुरू कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पाटिल की बैंच ने शुक्रवार को राज्य सरकार को सभी निलंबित और बर्खास्त कर्मचारियों को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता को इस मामले में अदालत की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है।

वकील अरविंद सेठी की ओर से गुरुवार को दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 नवम्बर की तारीख तय करते हुए बैंच ने हरियाणा सरकार से हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता बी.आर. महाजन ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाएगी। इससे पहले बैंच ने यूनियन के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की।

कोर्ट के आदेश के बाद हरि नारायण शर्मा सहित हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के चार नेताओं ने शनिवार सुबह 10 बजे से हड़ताल खत्म कर करने का आश्वासन दिया है। दरअसल, हरियाणा रोडवेज के करीब 19,000 कर्मचारी राज्य सरकार के निजी बस मालिकों की 700 बसें चलाने के निर्णय के खिलाफ 16 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं।

हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की समन्वय समिति ने गुरुवार को जींद में चार नवम्बर को 'रोडवेज बचाओ, नौकरी बचाओ रैली के आयोजन का फैसला किया था। रोडवेज की 4100 बसें हैं।

प्रदूषण से निपटने के तमाम उपायों के बावजूद दिल्ली की हवा ' 'बेहद खराब''

नई दिल्ली, एजेंसी। दिवाली पर प्रदूषण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में एहतियात के तमाम कदम उठाए गए हैं, उनके बावजूद वायु की गुणवत्ता शुक्रवार को भी ' 'बेहद खराब'' स्तर पर बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता 368 रिकॉर्ड की गई जो बेहद खराब की श्रेणी में आती है। वहीं, पीएम 2.5 का स्तर 210 दर्ज किया गया। यह कण पीएम 10 से भी छोटे होते हैं और स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में चार इलाकों में वायु गुणवत्ता ' 'गंभीर स्तर'' पर है जबकि 29 इलाकों में ' 'बेहद खराब'' दर्ज की गई है। केन्द्र द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (एसएएफएआर) के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पीएम 10 का स्तर 333 बना हुआ है।

अगले तीन और हालात और बिगड़ने के आसार

एसएएफएआर का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता इंडेक्स अगले तीन दिन तक 'बेहद खराब की श्रेणी में बना रहेगा। एसएएफएआर की वेबसाइट के अनुसार, ' 'यह मुख्य रूप से मौसमी हालात के कारण है क्योंकि पराली जलने की भागीदारी इसमें बहुत कम रह गई है। पश्चिमी विच्छोभ के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में नमी का बढ़ना और चार नवंबर तक जारी रहेगा।

»» हरियाणावासियों को मिली लाल डोरा से मुक्ति

खट्टर सरकार ने जनता को दिए ऐसे अनेक तोहफे

चंडीगढ़, एजेंसी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा दिवस पर प्रदेशवासियों को लाल डोरा से मुक्ति देने जैसी बड़ी राहत प्रदान करने तथा सभी पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों के प्रधानों को मासिक पेंशन देने, सभी चौकीदारों को आयुष्मान योजना में शामिल करने तथा लाइनमैन, सहायक लाइनमैन, फायरमैन, फायर ड्राइवर और सीवर मैन के जोखिम भरे काम के लिए उन्हें दस लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है।

केएमपी एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन 10 को

राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दस नवम्बर को सुबह साढ़े दस बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे।

लाल डोरा की व्यवस्था समाप्त

बेदी के अनुसार, राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए लाल डोरा की व्यवस्था समाप्त कर दी है जिससे अब गांवों के लाल डोरा से बाहर बने मकानों की रजिस्ट्री हो सकेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के तहत सभी पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों के प्रधानों को सम्मान के रूप में 1000 रुपये तथा अधिकतम 2000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसी तरह नगर निगमों के सभी पूर्व महापौर को भी हर अवधि के लिए 2500 रुपये तथा पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर, नगर परिषद के प्रधान को 2000 रुपये और नगर पालिका के पूर्व प्रधानों को 1000 रुपये, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन को 1500 रुपये, ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन को 1500 रुपये, पूर्व उप चेयरमैन को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन का तोहफा प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि ढाई साल या इससे अधिक के कार्यकाल पूरा करने वाले ही पेंशन के पात्र होंगे।

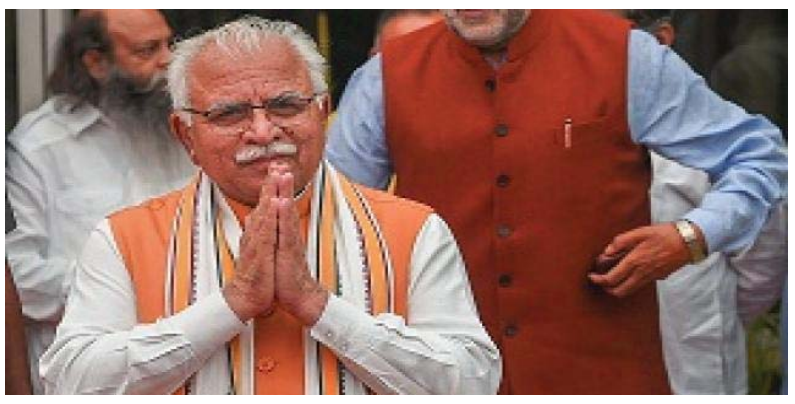

चौकीदरों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ

मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के नम्बरदारों को पहले ही आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर इस योजना का लाभ दे रही है। अब प्रदेश के चौकीदरों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार सभी लाइनमैन, सहायक लाइनमैन, फायरमैन, फायर ड्राइवर और सीवर मैन को उनका काम अधिक जोखिम भरा होने के कारण 10 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मुहैया कराएगी। इसका प्रीमियम सरकार वहन करेगी।

छात्रों के लिए कॉलेज में ही बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

वहीं, अब सभी छात्र-छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये लाइसेंस अब शिक्षण संस्थानों में ही बनेंगे। उन्होंने बताया कि सक्षम योजना में पहले पोस्ट ग्रेजुएट, गेजुएट में टेक्निकल और मेडिकल छात्रों को लाभ मिलता था। अब इसमें सभी ग्रेजुएट युवाओं को भी शामिल किया जाएगा।

ईंटों का खडंजा बिछाकार पक्के होंगे चकरोड

उन्होंने बताया कि खेतों में जाने वाले रास्तों (चकरोड) पर लाल ईंटों का खडंजा बिछाकार पक्का किया जाएगा। इसी वर्ष हर विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर लम्बे ऐसे रास्ते पक्के किए जाएंगे। इसके लिए 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने बताया कि खेतों में जाने वाले नहरी खालों को 24 फुट प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 फुट प्रति एकड़ किया गया है। सरकार अब 40 फुट प्रति एकड़ नहरी खाला बनाकर देगी।

सभी बीमारियों के लिए होगी कैश-लैस स्वास्थ्य सुविधा

उन्होंने बताया कि 20 नवम्बर, 2017 को हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों को छह तरह की बीमारियों के लिए कैश-लैस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अब इसका दायरा बढ़ाकर सभी बीमारियों तक करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की समूची योजना को कैश-लैस किया गया है।

भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार

जींद विधानसभा उपचुनाव को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ही चुनाव की तारीख तय करता है, इसमें सरकार किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है।

आरोप लगाने के बजाय परिवार को सम्भालें चौटाला

अभय चौटाला के आरोप को लेकर अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि वे परिवारिक बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि, वह यह जरूर कहना चाहेंगे कि चौटाला को किसी पर आरोप लगाने के बजाय परिवार को सम्भालना चाहिए। आज कोई बाहर का व्यक्ति या विपक्षी नेता नहीं बल्कि उनके अपने ही लोग विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सम्बंधित सवाल पर बेदी ने कहा कि केजरीवाल की हालत आज ऐसी है कि वे दिल्ली को बचा लें वही बड़ी बात है।

हुबली : बृहस्पतिवार को 63वें कर्नाटक राज्योत्सव समारोह के मौके पर कला का प्रदर्शन करतीं महिला कलाकार।

1000 ई-बसों के लिए टेंडर निकालने की योजना बना रही दिल्ली सरकार : गहलोत

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को प्रशिक्षण तौर पर ई-बस लॉन्च करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार दिसंबर तक 1000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर निकालने की योजना बना रही है, ताकि अगले पांच से छह महीने में शून्य उत्सर्जन वाहनों को सड़कों पर लाया जा सके। तीन माह के इस प्रशिक्षण में ई-बस अंबेडकर नगर टर्मिनल से इंद्रपुरी के बीच चलेगी। गहलोत ने पत्रकारों से कहा कि एक महीने में 'डेल्ही इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

»» परिवहन मंत्रालय साइकिल सवारी को देगा बढावा

14 लेन की सड़कों पर साइकिल के लिए अलग से लेन बनेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के साथ ही उनके मंत्रालय की राजमागरें और महानगरों में अलग लेन बनाकर लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि 14 लेन की सभी सड़कों पर साइकिल चालकों के लिए अलग से लेन बनाई जाएगी ताकि लोगों को साइकिल की सवारी करने में आसानी हो। इसके साथ ही नगरों और महानगरों में भी सभी मागरें पर अलग से साइकिल लेन तैयार करने की योजना है। साइकिल का लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें इसके लिए अभियान चलाया जाएगा और मशहूर हस्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा।

श्री गडकरी ने गुरुवार को यहां ओला इंस्टीट्यूट द्वारा 20 शहरों में आवागमन से जुड़े विभिन्न पक्षों पर किए गए सव्रेक्षण ''ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2018' की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा प्रदूषण रोकने के लिए उनका मंत्रालय इलेक्ट्रोनिक वाहनों को बढावा दे रहा है। इसके तहत ई-रिक्शा तथा ई ऑटो रिक्शा का सफल संचालन किए जाने के बाद अब ई-बसों को भी संचालित किया जा रहा है। इससे जहां वाहनों से निकलने वाले धुएं से मुक्ति मिलेगी वहीं तेल पर निर्भरता भी कम होगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि मंत्रालय में राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया साइकिल से ही संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने आते हैं। लोगों को इसी तरह से साइकिल से अपने काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

श्री गडकरी ने कहा कि सड़कों में अलग से लेन बनेगी तो बड़ी संख्या में लोग साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। दोपहिया वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी उपाय के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जब अलग से लेन होगी तो साइकिल का इस्तेमाल करने वालों को सुरक्षा संबंधी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि निजी वाहनों का इस्तेमाल लोग कम करें इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। सरकार इसके लिए अभियान चलाने पर विचार कर रही है।

अभियान के दौरान लोगों से कहा जाएगा कि साइकिल का इस्तेमाल न सिर्फ स्वास्य के लिए अच्छा है बल्कि यह प्रकृति के लिए भी अच्छा है। साइकिल का इस्तेमाल करने से प्रदूषण नहीं होगा और लोगों को स्वच्छ हवा में जीने का मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, इस दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके लिए जलमार्ग को बढावा दे रही है और इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हल्दिया तक जलमार्ग का आरंभ करेंगे। उनके मंत्रालय का प्रयास है कि अगले कुछ माह के दौरान प्रयाग में होने वाले महाकुंभ में यात्री वाराणसी से प्रयाग तक आने जाने के लिए जल मार्ग का इस्तेमाल करें।

संपादकीय

बैंक और सरकार के बीच मतभेद

सवरेच्च अदालत द्वारा केंद्र सरकार से राफेल लड़ाकू विमान की कीमत तथा ऑफसेट की जानकारी मांगना इस पर जारी कानूनी लड़ाई की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पूर्व में राफेल की जांच संबंधी याचिकाओं पर अदालत ने जो रवैया अपनाया था, उससे संभवत: सरकार को आभास हुआ कि अदालत मामले को उस रूप में नहीं ले रही है, जैसा याचिकाकर्ता चाहते हैं। तब अदालत ने केवल बंद लिफाफे में खरीद प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी, जिसे सरकार ने दे भी दिया। अब अदालत कह रही है कि किसी भी याची ने राफेल की गुणवत्ता और भारतीय वायु सेना में उसकी उपयोगिता पर सवाल नहीं उठाए हैं। चूंकि सवाल निर्णय लेने की प्रक्रिया और जो खरीद हुई है, उसकी कीमत पर उठाए गए हैं, इसलिए वह जानकारियां अदालत को चाहिए। स्वाभाविक था कि सरकार के रुख के अनुरूप महाधिवक्ता केके वेणुगोपाल इसमें असमर्थता व्यक्त करें। किंतु जब उन्होंने कहा कि कीमत से जुड़ी सूचनाएं इतनी संवेदनशील हैं कि उन्हें संसद के साथ भी साझा नहीं किया गया है, तो अदालत ने कहा कि कीमत से जुड़ी जानकारी विशिष्ट सूचना है, और आप उसे हमारे साथ साझा नहीं कर रहे हैं, तो शपथ पत्र देकर हमसे यह बात कहें। शपथ पत्र में सरकार को स्पष्ट करना होगा कि किन कारणों से कीमत नहीं बताना चाहती। देखना होगा कि 14 नवम्बर को होने वाली अगली सुनवाई में सरकार के शपथ पत्र में दिए गए कारणों पर अदालत क्या रुख अपनाती है। अगर अदालत कह रही है कि सरकार सामरिक महत्त्व की सूचनाएं छोड़कर सौदे के फैसले की प्रक्रिया को सार्वजनिक करे तो इसका मतलब है कि सीलबंद लिफाफे में खरीद प्रक्रिया की जो जानकारी दी गई उसे गोपनीय रखने के तर्क से वह सहमत नहीं है। इस आदेश के अनुसार सरकार को दस दिन में ये सूचनाएं याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करनी होंगी। इस तरह सरकार के सामने विकट स्थिति है। विरोधी दलों को जवाब देना आसान है, अदालत को नहीं। उसकी एक भी विपरीत टिप्पणी सरकार के लिए सियासी रूप से नुकसानदेह हो सकती है। सरकार के सामने राफेल पर अब विपक्ष के साथ अदालत में पेश हुई चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाने की स्थिति पैदा हो गई है। राफेल पर राजनीतिक एवं कानूनी मोर्चाबंदी इतनी आगे बढ़ गई है कि इसको तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक अदालत इस पर अंतिम मत नहीं दे देती।

''स्टैच्यू आफ यूनिटी'

आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निर्मित ''स्टैच्यू आफयूनिटी' का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित करना स्वागत योग्य कदम है। ऐसा करना सर्वथा उचित था, क्योंकि सरदार पटेल का योगदान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में ही नहीं, आजाद भारत के निर्माण में भी था। उन्होंने न केवल विभिन्न रियासतों को एक झंडे के तले लाकर भारत को नया स्वरूप प्रदान किया, बल्कि देश के निर्माण की दिशा भी तय की। इसलिए अपने ऐसे सपूत को प्रतिष्ठित करना लाजिमी है। वैसे भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन-प्रशासन के विभिन्न स्तर पर अपने महापुरु षों को समुचित सम्मान देना चाहिए, ताकि लोगों की भावना को अभिव्यक्ति मिल सके। जब किसी राष्ट्र के जीवन में कभी मुश्किल क्षण आता है, तब ऐसे ही मनीषी प्रेरणा के स्रेत बनते हैं और समाज लड़ने की शक्ति मिलती है। पटेल की स्थापित की गई इस प्रतिमा के पीछे भी मोदी सरकार के कुछ उद्देश्य थे। एक तो यह कि वर्तमान और भावी पीढ़ी को एकता का संदेश देना, ताकि देश को बांटने वाली ताकतों को निष्प्रभावी किया जा सके। इसके लिए पटेल आदर्श नायक हैं, जिन्होंने तमाम झंझावातों के बीच देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। इसके पीछे दूसरा संदेश यह अंतर्निहित था कि समाज को अपने नायकों को सम्मान देना चाहिए। पटेल भारतीय इतिहास के वह पात्र थे, जिन्हें लोक विस्मृत नहीं कर पाया था, लेकिन सत्ता के स्तर पर उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला था। मोदी सरकार ने अधूरे कार्य को पूरा किया। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को तो भारतीय समाज और राजनीति में जो स्थान मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी व्यथित हो सकते हैं कि उनके इस प्रयास पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति की गति को रोका नहीं जा सकता। अगर पटेल की प्रतिमा का निर्माण किसी राजनीति का हिस्सा है भी, तो इससे सरकार की सेहत पर कोई फ र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समाज इसे सकारात्मक भाव से ले रहा है। कुछ विपक्षी पार्टियां इस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, उनसे समाज में उनके प्रति नकारात्मक भाव ही पैदा हो रहा है।

''त्वरित सुधारात्मक एक्शन'

हाल ही में डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने भाषण में आरबीआई की स्वतंत्रता को लेकर कई सवाल उठाए थे। शायद इससे पहले उन्हें कम लोग जानते थे। यदि कुछ तनाव हो भी तो उसको प्राइवेट मंतण्रा द्वारा भी सुलझाया जा सकता था। इस तरह का संबोधन एक डिप्टी द्वारा वैसे भी उचित नहीं, जहां रिजर्व बैंक के सरकार से संबंधों की र्चचा हो। वह भी उस समय में जब एक अन्य महत्त्वपूर्ण संस्था से सरकार के संबंधों पर राजनैतिक टीका-टिप्पणी हो रही हो। यहीं से सरकार के साथ आरबीआई की तनातनी सार्वजनिक हुई। इस समय तनाव के जो दो प्रमुख मुद्दे नजर आ रहे हैं, वह हैं-सरकार द्वारा पेमेंट रेग्युलेटर अलग से बनाए जाने की कवायद और बैंकों पर हाल में लगाए गए अंकुश।

सतीश पेडणोकर

आज तक इतनी समानता कभी नजर नहीं आई, जितनी कि इस समय नजर आ रही है। यह समानता आतंकवाद को लेकर नहीं है, और न ही दो बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर है। यह समानता अमेरिका के केंद्रीय बैंक और भारत के केंद्रीय बैंक के सरकार से संबंधों को लेकर है। अमेरिका में ''फेडरल रिजर्व' के चेयरमैन पॉवेल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन की बात को नहीं सुन रहे हैं। इधर, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अपने मन की कर रहे हैं, और सरकार के मन की बात नहीं सुन रहे हैं।

हाल ही में डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने भाषण में आरबीआई की स्वतंत्रता को लेकर कई सवाल उठाए थे। शायद इससे पहले उन्हें कम लोग जानते थे। यदि कुछ तनाव हो भी तो उसको प्राइवेट मंतण्रा द्वारा भी सुलझाया जा सकता था। इस तरह का संबोधन एक डिप्टी द्वारा वैसे भी उचित नहीं, जहां रिजर्व बैंक के सरकार से संबंधों की र्चचा हो। वह भी उस समय में जब एक अन्य महत्त्वपूर्ण संस्था से सरकार के संबंधों पर राजनैतिक टीका-टिप्पणी हो रही हो। यहीं से सरकार के साथ आरबीआई की तनातनी सार्वजनिक हुई। इस समय तनाव के जो दो प्रमुख मुद्दे नजर आ रहे हैं, वह हैं-सरकार द्वारा पेमेंट रेग्युलेटर अलग से बनाए जाने की कवायद और बैंकों पर हाल में लगाए गए अंकुश।

सरकार का अपना मत हो सकता है। सरकार को भी अपनी नीतियों से आरबीआई को अवगत कराए जाने का हक है, और अपनी नीतियों को बनाते हुए केंद्रीय बैंक को उनका संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। दोनों में मतैक्य आवश्यक है। दोनों का एक पेज पर होना जरूरी है। यही समस्या अमेरिका में भी है। फेडरल रिजर्व लगातार चौथी बार ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दे रहा है। कुछ जाने-माने विचारक मानते हैं कि फेडरल रिजर्व की स्वायत्तता का उपयोग डोनाल्ड ट्रंप को अपदस्थ करने की कोशिश भी हो सकती है। प्रकारांतर से मोदी सरकार को भी आरबीआई से खतरा महसूस हो रहा है। मेरे विचार से आरबीआई और सरकार के मध्य अन्य कई और कारण भी हैं, जो इस तनाव के रूप में लक्षित हुए हैं। ये कारण सार्वजनिक तो नहीं हुए हैं, मगर हो सकता है कि इन बातों का भी असर हुआ हो। उन बातों में से एक कोटक महिंद्रा बैंक में प्रोमोटर की हिस्सेदारी को घटाने के लिए प्रस्तावित बांड इश्यू को अनुमति दिया जाना हो सकता है।

बड़ी अजीब स्थिति है कि आईएलएफएस जैसे बड़े घोटाले को संभालने के लिए उदय कोटक की सेवाएं ली जाएं और उन्हीं के प्रस्तावों को संदेह से देखा जाए। न केवल यह, बल्कि दो बड़े माइक्रो फाइनेंस उपक्रमों को ''रिवर्स मर्जर' की अनुमति न देकर उन्हें अपनी बैंकिंग सेवाओं के लिए आईपीओ की बाध्यता को लागू करना। ये समस्त बातें व्यवसाय हेतु व्यावसायिक निर्णयों में बाधा डालना अधिक प्रतीत हो रही हैं। रिजर्व बैंक के पास इस संदर्भ में अपने वैध तर्क हो सकते हैं। मगर यह स्पष्ट है कि इस संबंध में उसकी कोई बात सरकार से नहीं हुई है। वित्तीय समावेशन एक सामाजिक एवं आर्थिक विषय से अधिक एक राजनैतिक मुद्दा भी है। रूरल इलाके वर्तमान सरकार के लिए इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं, और माइक्रो फ इनेंस कंपनियों का उसमें बहुत महती योगदान रहा है। रिजर्व बैंक के निर्णयों से स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों की जोरदार पिटाई हुई है, और वह पूंजी बाजार से कैपिटल लेने लायक नहीं बची हैं। जिस सेक्टर को मोदी सरकार से इनाम की दरकार थी, वह सजा पा रहा है। यह बात भी सरकार की चिंता बढ़ाने वाली और रिजर्व बैंक को अपनी नाराजगी से अवगत करानी जरूरी थी। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर कहीं न कहीं सरकार की नींद डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल में उड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक ट्वीट करके वह सब हासिल कर सकते हैं, जो कि वित्त मंत्री को आरबीआई एक्ट की स्पेशल पॉवर इस्तेमाल करके करनी पड़ी। आज तक कभी भी सरकार को सेक्शन 7 को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। मगर ध्यान देने वाली बात है कि इसका प्रावधान था। इस प्रावधान का उपयोग अपने आप में इस बात का संकेत है कि आरबीआई पर्याप्त रूप से स्वतंत्र है, और कठपुतली नहीं है। एक अन्य समस्या बैंकों को ''त्वरित सुधारात्मक एक्शन' द्वारा नियंत्रित करने को लेकर भी है। सरकार का कहीं न कहीं ऐसा मानना है कि आरबीआई का यह निर्णय गलत साबित हुआ है। इसका उल्टा असर हुआ है। अगर बैंक ऋण देने में ही असमर्थ रहें। नई शाखाएं न खोल पाएं।

भर्ती न कर पाएं तो वो लाभ कैसे कमा पाएंगे? तुलनात्मक रूप से उनका एनपीए बढ़ता ही जाएगा। अब जरा कोई रिजर्व बैंक से पूछे कि उसने जिस अधिकार से ग्यारह सरकारी बैंकों की स्वायत्तता छीनी अगर उसी अधिकार का प्रयोग सरकार उस पर करे तो? क्या रिजर्व बैंक सबसे ऊपर है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है? लगता है कि रिजर्व बैंक खुद को संप्रभुता से भी ऊपर मान कर चल रहा है। यह बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं। सारे ज्ञानी रिजर्व बैंक में ही भरे पड़े हैं क्या? गवर्नर साहब को और विशेष तौर पर डिप्टी गवर्नर साहब को यह समझना होगा कि भारत अमेरिका नहीं है, और न ही वह पॉवेल हैं। भारत में सामाजिक ऋण व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी बैंक एवं माइक्रो फ इनेंस कंपनियां जरूरी हैं। शायद यही संकेत वित्त मंत्री ने गवर्नर को अपनी मुलाकात में दिए होंगे। जनता सरकार को अपने कल्याण हेतु चुनती है। रिजर्व बैंक जनता की भावनाओं का संरक्षक नहीं है। एक रेग्युलेटर मात्र है। जनता के कल्याण के प्रति सरकार उत्तरदायी है न कि रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को अपने निर्णयों में चुनी हुई सरकार के प्रति जनता की अपेक्षाओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। विश्व में ट्रेडवॉर धीरे-धीरे गहराता जा रहा है। किसी भी युद्ध में सेना और सरकार अगर एकमत न हों तो देश की समस्त सुरक्षा एवं संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। मिलिट्री युद्ध में सेनाध्यक्ष एवं आर्थिक युद्ध के मौसम में रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच ही अगर संवाद न हो तो काफी खतरनाक स्थिति ही कही जाएगी। सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग कर रिजर्व बैंक से संवाद स्थापित किया। यह सुखद स्थिति तो नहीं मगर आवश्यक अवश्य है।

आज उदारवाद से संरक्षणवाद की ओर विश्व जा रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक को विदेशी शिक्षा से प्राप्त अपनी बुद्धि के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से अपने सीधे अनुभवों को स्थापित करना होगा। समस्त आर्थिक शक्ति ''बॉटम ऑफपिरामिड' में है। इस तय को जमीन से जुड़े राजनेता अच्छे से समझते हैं। रिजर्व बैंक अहंकार त्याग कर सरकार व राजनेताओं से बातचीत कर उनके स्वदेशी विचारों को निर्णयों में समाहित करना ही चाहिए।

चलते चलते

थकान

धांधली से मुक्त करने के तमाम प्रयासों में तंत्र को मुंह की खानी पड़ी है। बोर्ड से लेकर एसएससी तक फू लप्रूफ व्यवस्था के दावों के बावजूद लीकेज, निगरानी तंत्र को मुंह चिढ़ाते हैं। आए दिन परीक्षा परिणामों पर रोक के लिए न्यायालय में यचिका दायर की जाती है। पारदर्शिता के तमाम दावे धांधली उजागर होने के बाद तार-तार होते नजर आते हैं। दरअसल, जब सवाल एक अदद सरकारी नौकरी का हो तो रकम इसकी गारंटी बन जाती है। भंडाफोड़ होने के बाद नेता से लेकर अधिकारी तक जांच में दोषी पाए पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सपा और बसपा सरकारें पुलिस-पीएससी महकमे में हुए चयन को अपनी बारी आने पर पलट देने के लिए चर्चित रही है। अनियमितता का ताजा मामला बिहार से है, जहां पटना उच्च

आए दिन परीक्षा परिणामों पर रोक के लिए न्यायालय में यचिका दायर की जाती है। पारदर्शिता के तमाम दावे धांधली उजागर होने के बाद तार-तार होते नजर आते हैं। दरअसल, जब सवाल एक अदद सरकारी नौकरी का हो तो रकम इसकी गारंटी बन जाती है। भंडाफोड़ होने के बाद नेता से लेकर अधिकारी तक जांच में दोषी पाए पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सपा और बसपा सरकारें पुलिस-पीएससी

न्यायालय ने बिहार पुलिस अवर सेवा भर्ती आयोग द्वारा जारी मुख्य परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर दिया। पटना हाईकोर्ट में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दायर याचिका में कहा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में पिछड़ी जाति की एक भी महिला सफल नहीं हुई, लेकिन मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो उसमें 291 पिछड़ी जाति की महिलाओं के नाम थे। यह खुल्लम-खुल्ला धांधली थी। अच्छी बात यह रही कि न्यायालय ने पूरी परीक्षा रद्द नहीं की, बल्कि आपत्तियों को दूर कर फि र से परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। साथ में एक निगरानी कमेटी के गठन का भी आदेश दिया है। तकलीफ की बात है कि इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने में राज्य सरकार का रवैया टालमटोल वाला रहा जबकि यह उच्चस्तरीय अनियमितता का मामला है। अगर निष्पक्ष जांच हुई तो कई रसूखदार इसकी आंच को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मगर निष्पक्ष प्रशासनिक जांच खानापूर्ति की औपचारिक पहल मात्र बनकर रह गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं का रैकेट चलाने का कुख्यात रंजीत डॉन जैसा कई दलाल आज बाहर है। संभव है, इस मामले का मास्टरमाइंड भी बच निकले। मगर छात्रों के दुख से जिम्मेदार महकमे के अधिकारी कब रुदन करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा।

फोटोग्राफी...

तिरुवनंतपुरम : सबसे बुजुर्ग अभ्यर्थी के तौर पर राज्य संचालित लिटरेसी मिशन अथॉरिटी एग्जाम में शामिल होकर 100 में से 98 अंक प्राप्त करने वाली 96 वर्षीय कार्थियायनी अम्मा को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन।

सत्संग

''लाउडस्पीकर'

आपसे एक आसान-सा सवाल पूछते हैं, आपका सबसे करीबी मित्र कौन हैं? आपका उत्तर हो सकता है, ''मेरी पत्नी या मेरे पति, मेरा बच्चा। नहीं, नहीं, मेरा मित्र। न, न, मेरी मां हैं, पिता हैं।' इस तरह आप जो भी उत्तर दें, वह सब सफेद झूठ है। देखिए, उनमें से हरेक को आपने एक हद तक ही छूट दी है। किसी को घर के दरवाजे तक, किसी को अपने हाथ की पहुंच तक, किसी को अपने बिस्तर तक। लेकिन चाहे कितनी ही नजदीकी क्यों न हों, उनसे भी एकाध रहस्य आपने अपने मन में छिपा रखा है। उस रहस्य को भी जानने की हद तक आपसे निकटता रखने वाला व्यक्ति केवल एक ही है। कौन हैं वह? ''वह ईर हैं'-ऐसे मूर्खतापूर्ण उत्तर मत दीजिएगा। आपके रहस्यों को जानने के बजाय दूसरे महत्त्वपूर्ण काम उनके पास हैं। तो, फि र वह करीबी व्यक्ति कौन है? और कौन? आप खुद हैं। हां, आप ही हैं! आप से भी घनिष्ठ व्यक्ति आपके लिए और कौन हो सकता है? आपको उसी घनिष्ठ व्यक्ति के बारे में ही पूर्ण रूप से जानना चाहिए। हर क्षण को अपनी इच्छानुसार बना लेने के लिए आपको दिया गया अवसर ही है यह जीवन। इस पृवी के भाग्य को बदलने वाले सभी ज्ञानी, उस क्षण के लिए जो आवश्यक था, उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण इच्छा के साथ लग गए। वे यह सोच कर इंतजार में नहीं बैठे रहे कि पचास, पांच सौ या पांच हजार साल बाद कोई उस काम को करेगा। इस देश के सारे ''लाउडस्पीकर' उन्हीं लोगों के थोथे बोल का शोर मचा रहे हैं, जो किसी तिनके को उठाकर रखने के लिए भी तैयार नहीं रहते। आज का माहौल हम सबके लिए इतना अनुकूल है, जितना पहले कभी नहीं रहा था। विज्ञान ने हमें इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि एक साथ मिल कर काम करने में भाषा, संस्कृति, दूरी आदि कुछ भी बाधक नहीं है। अगर आप जागरूकता से, आनंद से, लगन से और एकाग्र होकर काम करने लग जाएं तो आपके चारों ओर सौ लोग काम करेंगे। उनके चारों ओर दस हजार लोग सशक्त हो जाएंगे। यह संख्या थोड़े ही समय में दस लाख बन सकती है। अगर दस लाख लोग जिम्मेदारी की भावना से पूरी लगन के साथ काम करेंगे तो उसके टक्कर की मजबूत ताकत विश्व में और कोई नहीं हो सकती। यह कहने की जरूरत नहीं है। दरअसल, अपराजेय सैन्य बल रखना ताकत नहीं है। सही मार्गदर्शन पाने के लिए लोग आपकी तरफ ताकते हैं, वही है सबसे बड़ी ताकत।

लालच में बुद्धि भ्रष्ट

ईमानदारी और मेहनत से कोई भी काम करके पैसा कमाना गलत है। जितना मर्जी चाहें पैसा कमाएं, सरकार या किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जल्दी-जल्दी येन-केन-प्रकारेण पैसा कमाने की फि राक में अपराधी बन जाना या अनैतिक हथकंडे अपनाना तो गलत है ही। इसी विकृत मानसिकता के चलते ही कुछ बेहद संभावनाओं से लबरेज पेशेवर और उद्यमी भी बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। अब पेटीएम के चेयरमेन विजय शेखर को ब्लैकमेल कर 20 करोड़ रु पये मांगने की आरोपित सोनिया धवन को ही लीजिए। वह विजय शेखर की निजी सहयोगी थीं। कड़ी मेहनत करके अपने कॅरियर में आगे बढ़ रही थीं। उनकी सैलरी सालाना 60 लाख रु पये तक हो गई थी। पेटीएम में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पहुंच गई थीं। पर फि र झाटा दौड़ के धावक की तरफ पैसा कमाने के लिए तेज दौड़ लगाना चाहती थीं। मतलब यह कि एक झटके में ही करोड़ों रु पये जेब में डाल लेना चाहती थीं। इसलिए उनने अपने संरक्षक से ही 20 करोड़ रु पये की फि रौती मांगने का महा घृणित षड्यंत्र रचा। जरा बताइये कि कितने भारतीय सालाना 60 लाख रुपये कमा पाते हैं? पांच लाख रुपये महीना कमाने वाली सोनिया को समझ नहीं आया कि संतोष का क्या आनंद होता है? कुछ साल पहले हैदराबाद स्थित आईटी कंपनी सत्यम में घोटाले ने सारे देश को हिला कर रख दिया था। भारत में सत्यम जैसा बड़ा कॉरपोरेट घोटाला कभी पहले नहीं हुआ था। सत्यम के संस्थापक बी. रामलिंगा राजू ने खातों में गड़बड़ी करके करोड़ों रुपये का मुना फा कमाया था। दरअसल, रामलिंग राजू ने रीयल एस्टेट में मोटा पैसा लगाना शुरू कर दिया था। इससे कुछ लोगों को शक हुआ कि वे आईटी बिजनेस में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं।

राजू को 7 जनवरी, 2009 को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब सत्यम में 8 हजार करोड़ रुपये का घपला सामने आया था। दरअसल, लालच के दैत्य ने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। वे भारत की आईटी क्रांति के अग्रणी हस्ताक्षर थे। यदि अपना कामकाज पूरी ईमानदारी से करते रहते तो वे भी एन. नारायणमूर्ति और नंदन नीलकेणी सरीखे आईटी क्षेत्र के महान हस्तियों के रूप में जगह बना लेते।

आप गौर कर रहे होंगे कि बीते कुछ समय में एक के बाद एक ऐसे केस सामने आ रहे हैं, जिनमें कोई खास और सफल शख्सियत भी फं सी होती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन सुशील मनहोट को भी करप्शन के कथित आरोपों के कारण ही हटाया गया। अब रीयल एस्टेट सेक्टर में फैली लूट को भी देख लीजिए। अब लगभग रोज ही कुछ कथित नामवर बिल्डरों की कलई खुल रही है। इन्होंने अपने ग्राहकों के साथ धोखा करना शुरू कर दिया। नोएडा में सैकड़ों बिल्डर खुलेआम ग्राहकों को लूटते रहे। उन्हें अपनी छतों का सब्जबाग दिखाते रहे। बिल्डरों के मारे ग्राहक रो रहे हैं अपनी किस्मतों पर। कुछ बिल्डरों को जेल भी भेजा चुका है। ज्यादातर बिल्डरों का कामकाज पारदर्शी नहीं होता। हवस का तो इलाज ही नहीं है। ''मेरा घर मेरा हक' का नारा देने वाले आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा की ही बात कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ समय पहले शर्मा को ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में जेल भी भेज चुका है। लगता है कि लालच में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सही कहा गया है कि ''लालच बुरी बला है।' स्पष्ट है कि येन केन प्रकारेण धन कमाने की मानसिकता पर लगाम लगाने की जरूरत है।

दुनिया के 6 खतरनाक

आइलैंड

यहां जाने से पहले सैकड़ों बार सोचेंगे आप!

दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें है जहां लोग अपना हॉलिडे एन्जॉय करने जाते है। जहां कि खूबसूरती और बीच लोगों को बहुत ही भाते है लेकिन दुनियाभर में कई जगहें ऐसी होती है जहां भूतों का आंतक तो कहीं जहरीले सांप। ऐसे में इन जगहों पर घूमना खतरा मौल लेने की बात है। आज हम आपको ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताएंगे जहां चलता है इन्हीं चीजों का राज...

1.स्नेक आइलैंड, ब्राजील

इल्हा दे ब्राजील क्रेइमाडा ग्रैंड समुद्र के बीचों-बीच बना आइलैंड है। इस जगह पर इंसानों के बदले सिर्फ सांप रहते हैं। यहां पर 4,000 प्रकार के अलग-अलग सांप पाए जाते हैं, जो अपने जहर से किसी की भी जान लेने में माहिर हैं। ब्राजील गवर्नमेंट ने इस जगह परजाना बैन किया हुआ है ल्किन फिर भी लोग चोरी-छुपे इस आइलैंड पर जाते हैं

पे इस आइलैंड पर जाते हैं।

2.रीयूनियन आइलैंड

यह आइलैंड महासागर के बीच बसा है और यहां की आबादी एक मिलियन से भी कम है। हालांकि ये आइलैंड पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन में शुमार है लेकिन इस 40 मील लंबे आइलैंड में शार्क की मौजूदगी चिंता का विषय है। इस शार्क ने अब तक ना जाने कितनों लोगो पर हमला करके उनको घायल किया है।

3.प्रोवेग्लिया आइलैंड

इटली के प्रोवेग्लिया आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहां जाने वाला जिंदा वापस नहीं आता। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को जिंदा जला दिया जाता था। यहां घूमने वालों को कई भुतहा चीजें नजर आती है।

4.ग्रुइनार्ड आइलैंड

स्कॉटलैंड की खाड़ी में बसा छोटा सा द्वीप है ग्रुइनार्ड। ये आइलैंड करीब 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। कुछ साल पहले यह आइलैंड हरा-भरा होता था लेकिन आज ये आइलैंड बिल्कुल वीरान हो चुका है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने इस आइलैंड पर एंथ्रेक्स नाम के जहरीले गैस का परीक्षण किया था, जिसकी वजह से यहां जाना खतरनाक है।

5.इजू आइलैंड

जापान का मियाकेजीमा इजू आइलैंड अपने अजीबों-गरीब व्यवहार और टूरिज्म के लिए फेमस है। यहां का हर इंसान मास्क पहने दिखता है लेकिन मियाकेजीमा आइलैंड पर एक बेहद ही सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ओयामा है। यहां कई बार बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हो चुके हैं। जिसमें लावा के साथ-साथ बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें निकलती है।

6.साबा आइलैंड

कैरिबियाई सी के बीच में मौजूद इस आइलैंड खूबसूरती देखने लायक है लेकिन तूफान के कारण यह जगह सबसे खतरनाक हैं। यहां की जमीन कभी भी डोलने लगती है इस वजह से माना जाता है की आइलैंड में कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है।

मानसून

में घूमने के लिए बैस्ट हैं ये प्लेस

मानसून आने से तपती धूप और गर्मी से रहत तो मिलती है। इस खूबसूरत मौसम में प्राकृति का नजारा भी मन को खूब भाता है। ऐसे में जहां कुछ लोग घर में रहकर चाय-पकौड़े खाना पसंद करते हैं, वहीं घूमने के शौकिन लोग ऐसी जगहों पर जाने का प्लान बनाते है। जहां पर कुदरती नजारों का खुलकर लुत्फ उठाया जा सके। आज हम आपको भारत की ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहें हैं,जहां आप मानसून का भरपूर मज़ा ले सकते हैं।

1.गोवा

गोवा में बारिश के मौसम में घूमने की बात ही अलग है। बारिश की फुहारों और ठंडी हवाओं में यहां के बीच पर घूमना काफी अच्छा लगता है अगर आपको धीमी-धीमी बारिश मिल जाए, तो इस मौसम का मजा दोगुना हो जाता है।

2.दार्जिलिंग

दार्जिलिंग भारत के मशहूर टूरिज्म स्थानों में से एक है। चाय के बागान बारिश में और भी सुंदर लगते हैं। यह सैलानियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है।

3.लेह-लद्दाख

लेह-लद्दाख मानसून में घूमने के लिए एक शानदार जगह है। इस खुशनुमा मौसम में यहां पर आपको प्रकृति के असली रंग देखने को मिलते हैं। 4.उदयपुर

उदयपुर राजस्थान की खूबसूरत जगहों में से एक है। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।

5.लोनावाला

लोनावाला देशों के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। इसे महाराष्ट्र का स्विटजरलैंड भी कहा जाता है। यहां पर आप बारिश के दिनों में प्रकृति को काफी करीब से महसूस कर सकते हैं।

6.पुडुचेरी

बारिश के मौसम में पुडुचेरी घूमने का अपना अलग ही मजा है। यहां पर देखने के लिए कई स्मारक, खूबसूरत मंदिर और बीच भी है।

7.शिलांग

शिलांग के सुहाने मौसम के कारण इसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है।

चीन ने बना लिया दुनिया का सबसे बड़ा

कांच ब्रिज

चीन अपने हैरतअंगेज कामों के कारण हमेशा से ही सुर्खियो में रहा है। चीन ने हुनान प्रांत में दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा कांच का पुल बनाया गया है। ग्लास बाटम से बने इस पुल को 2 पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। मजबूती में तो इस पुल की कोई बात नही। इसकी मजबूती को जांचने के लिए कम से कम 20 लोगो ने इस पर हथौड़ो से वार इस पर कुछ निशान तो पड़े लेकिन इसके अलावा इसकी मजबूती को कोई भी फर्क नही पड़ा। सुरक्षा परीक्षण के लिए चीनी अधिकारियों ने इस पर दो टन वजन के ट्रक को चलाया और यह परीक्षण भी सफल रहा। इस पुल की ऊंचाई जमीन से 300 मीटर की है।

इस ब्रिज पर चलने से इसकी गहराई साफ दिखाई देती है और कुछ लोग तो इस पुल पर चलने से कतराते हैं। इस 3 मीटर लंबे, 4.5 मीटर चौड़े और 15 मिमी मोटाई वाले टेम्पर्ड ग्लास के कुल 99 टुकड़े लगाए गए हैं। यह ब्रिज वाकई में अदभूत है।

एक ऐसी जगह, जहां समुद्र के अंदर हिन्दुओं के धार्मिक स्थल!

वैसे तो हिन्दुओं के धार्मिक स्थल पूरी दुनिया में फैले है लेकिन आपको यह जान कर हैरानी होगी कि हमारे संसार में एक जगह ऐसी है जहां आपको समुद्र के नीचे भी धार्मिक स्थल दिखाई देगे, जिनका विस्तार आकाश और धरती तक हुआ है। आइए जानते और देखते समुद्र के नीचे बने इन धार्मिक स्थलों के बारे में...

इंडोनेशिया के समुद्र के नीचे बनी भगवान् विष्णु की मूर्ति लगभग 5000 हजार साल पुरानी बताई जाती है। लोग स्विमिंग करते समय इनके दर्शन करने जरुर आते है।

यहां समुद्र के नीचे बने एक खँडहर को देखकर लगता है जैसे यह द्वारिका नगरी हो सकती ह।क्योंकि द्वारिका नगरी समुद्र तट पर बसी थी और सुमद्र के अंदर विलीन हो गई थी। इस जगह पर यह शिव मूर्ति भी समुद्र के अंदर ही मिली, जो इस जगह पर उस समय की जाने वाली शिव पूजा को दर्शाता है और लोग इसको देखने के लिए भी आते है।इन सब को देखकर लगता है यहां कोई प्रचीन नगरी रही होगी, जो समुद्र के समीप या अंदर होने के कारण यहां डूब गयी होगी।

सूरत। सूरत शहर जिला कांग्रेस समिति द्वारा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति और भाजपा शासकों के भ्रष्टाचारी और घमंडी शासन के सामने एक दिन का प्रतिक धरणे का कार्यक्रम एन.प्रा.शाला समिति गोपीपुरा में रखा गया। जिसमें बड़ीं संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया।

सूरत। नर्सिंग की छात्राओं द्वारा दिवाली की रंगोली बनाई सिविल होस्पिटल सूरत।

26 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने प्रभारियों की नियुक्ति

सूरत। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुजरात की सभी 26 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए भाजपा ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। साथ ही इंचार्ज और सह इंचार्जों को भी नियुक्त किया है। अन्य जिलों के पदाधिकारियों को अन्य जिलों का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जिला प्रमुख, महासचिव, प्रदेश भाजपा की ओर से नियुक्त प्रभारी संकलन कर सभी 26 सीटें जीतने का साथ मिलकर प्रयास करेंगे।

गुजरात प्रदेश भाजपा ने भरत बारोट को सूरत का प्रभारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार नवसारी में निरंजन झांझमेरा, वलसाड में विवेक एन पटेल, राजकोट में नरहरि अमीन, पोरबंदर में रमेश मुंगरा, जामनगर में रमणलाल वोरा, जूनागढ़ में रमेश रूपापरा, अमरेली में जयंती कावडिया, भावनगर में महेश कसवाला, आणंद में अमित शाह (अहमदाबाद के पूर्व महापौर), खेडा में जयसिंह चौहाण, वडोदरा में जयनारायण व्यास, छोटाउदेपुर में रमेश मिस्त्री, भरुच में प्रफुल पानसेरिया, बारडोली में पूर्णेश मोदी, पंचमहल में पराक्रमसिंह जाडेजा, दाहोद में अमित ठाकर, कच्छ में बिपिन दवे, बनासकांठा में दुष्यंत पंड्या, पाटण में मयंक नायक, मेहसाणा में जगदीश पटेल, साबरकांठा में प्रदीपसिंह वाघेला, गांधीनगर में पृथ्वीराज पटेल, अहमदाबाद पूर्व में डॉ. जीवराज चौहाण और अहमदाबाद पश्चिम में आईके जाडेजा तथा सुरेन्द्रनगर का बतौर प्रभारी नितिन भारद्वाज को नियुक्त किया गया है।

आंगडिया कर्मचारी से 13 लाख की लूट

अहमदाबाद। ऊना-भावनगर रोड पर आंगडिया फर्म के एक कर्मचारी से नकद और हीरा समेत रु. 13 लाख की लूट चलाकर बाइक सवार तीन श स फरार हो गए। खबर पाते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक पी. शैलेष नामक आंगडिया फर्म के कर्मचारी विष्णु बालुभाई पटेल ऊना-भावनगर रोड से गुजर रहे थे। उस वक्त एक ही बाइक पर आए तीन श सों ने विष्णु पटेल को धक्का मार दिया। विष्णु पटेल के सड़क पर गिरते ही बाइक सवार तीन शख्स उनके पास पहुंच गए और रु. 1000000 नकद और रु. 300000 कीमत के हीरा समेत रु. 1300000 की लूट चलाकर फरार हो गए।

सूरत। शहर में इन दिनों हलकी ठंडी का अहसास होने लगा है जिसे देखते हुए उनी कपड़ों की बाजार सजने लगी है और लोगो ने भी सर्दी से बचने के लिए उनी कपड़े खरीदने शुरु कर दिए है। शुक्रवार को भींडी बाजार चौक में उनी कपड़ों की दुकान पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली।

सवजी धोलकिया के नाम पर ठगी का प्रयास, पुलिस जांच शुरू

सूरत। शहर के मशहूर डायमंड किंग सवजी धोलकिया के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल किसी शख्स ने सवजी धोलकिया के नाम से फेसबुक पर फर्जी एकाउंट बनाया था और उसके जरिए लोगों से रुपए ऐंठने की योजना बनाई थी। लेकिन धोलकिया को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने फौरन क्राइम ब्रांच में शिकायत कर दी।

सूरत के हीरा कारोबारी सवजी धोलकिया ने हाल ही में अपने 600 कर्मचारियों को दिवाली बोनस में कार गिफ्ट की है। सवजी धोलकिया ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, हर साल वह अपने कर्मचारियों को महंगी गिफ्ट देते आए हैं धोलकिया के नाम को भुनाने के लिए एक अज्ञात शख्स ने फेसबुक पर उनके नाम से फर्जी एकाउंट बनाया, जिसमें लिखा कि सवजी धोलकिया ने एक स्कीम शुरू की है। स्कीम के तहत रु. 8000 भरकर स्विफ्ट गाडी प्राप्त करें। स्कीम के उल्लेख साथ सवजी धोलकिया की तस्वीर भी फर्जी फेसबुक अपलोड की गई थी। कंपनी के मैनेजर को इसकी भनक लगी तो उन्होंने सवजी धोलकिया के नाम से फेसबुक पर फर्जी एकाउंट बनाने वाले का पता लगाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिलने पर सूरत क्राइम ब्रांच में मामले की शिकायत कर दी। क्राइम ब्रांच ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की है।

सूरत। स्वच्छ भारत और स्वच्छ सूरत के तरह लगाई गई कचरे की पेटीयों की हालत कुछ ही दिनों में दैनीय हो गई है ये कचरा पेटी शहर की लगभग सभी इलाकों में लगाई गई है लेकिन इनकी कवालीटि खराब होने के कारण ये जगह-जगह से टुट चुकी है। शहर के अठवा लाइन इलाके में लगाई गई कचरा पेटी की फोटों।

15 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

अहमदाबाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 15 दिसंबर को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने गुजरात आएंगे। नर्मदा बांध के निकट साधू बेट पर सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे विराट मूर्ति का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर को इसका अनावरण किया था।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक देश की एकता-अखंडता के प्रतीक सरदार साहेब की प्रतिमा स्टेच्यु ऑफ युनिटी निहारने के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 15 दिस बर को गुजरात आ रहे हैं। वाइब्रेंट समिट से पूर्व विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गुजरात आएंगे इसी सिलसिले में आजशुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मु यमंत्री योगी आदित्यनाथजी भी केवडिया सरदार साहेब के दर्शनार्थ गुजरात आए हैं। उन्होंने कहा कि आनेवाले दिनों में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, वरिष्ठ सचिव, उद्योगपतियों सहित समाज के अग्रणी महानुभाव और नागरिक और कलाकार भी स्टेच्यु ऑफ युनिटी पहुंचकर सरदार साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करें, इस प्रकार का आयोजन किया गया है।

योगी आदित्यनाथ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देश की वैश्विक पहचान हैं : योगी

अहमदाबाद । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नर्मदा जिले के केवडिया कोलोनी में स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे । पर्यटोकों के लिए भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खुल चुकी है तब आज उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ने सरदार साहब और गुजरात की गरीमा को बढ़ा दिया है। उन्होंने यह भी कहा की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र की विश्व स्तर पर एक पहचान बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने भारत की एकता और अखंडता के प्रतिक रहे सरदार पटेल की प्रतिमा को उत्सुकतापूर्वक देखा।

सरदार पटेल की विराट प्रतिमा को देखकर योगी आदित्यनाथ भी आश्चर्यचकित हो गए । इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी उनके साथ रहे । विजय रुपाणी और अन्यो ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। विजय रुपाणी ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वेली ऑफ फ्लावर्स, टेन्ट सिटी, सरदार पटेल के जीवन पर प्रदर्शन, वॉल ऑफ युनिटी समेत के पुरे परिसर में घुमकर जानकारी ली। योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता के शिल्पी की विराट प्रतिमा राष्ट्र की वैश्विक पहचान बन चुही है ।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साहस और दिर्धकालीन आयोजन की प्रशंसा की। मोदी ने प्रतिमा का निर्माण कराकर पटेल और गुजरात का गौरव दुनिया में बढ़ाया है । योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारो के साथ बातचीत में कहा कि ५६२ राजा महाराजा की संपत्ति और उन्हें एकत्रित करते हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधा था । उनके इस प्रयास को युगो युगो तक याद किया जाएगा और युवा पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी । सरदार पटेल की कल्पना को सरदार सरोवर बांध के निर्माण के साथ ही साकार करके मोदी ने गुज रात के किसानो को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। गुजरात की समृद्धि के द्वार खुल गए है। योगी आदित्यनाथ और रुपाणी के साथ इस अवसर पर सरकार के अन्य अफसर और अधिकारी भी दिखे ।

गुजरात सरकार का एक और महत्वपूर्ण निर्णय

पंचायत विभाग के तलाटी की वेतन की विसंगतता दुर

अहमदाबाद। गुजरात के उपमुख्यमंत्री नीतिनभाई पटेल ने आज कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के प्रश्नो को हमेशा महत्व दिया है। कर्मचारियों के प्रश्नो को लेकर हमेशा उदार द्रष्टीकोण रखा है। उन्होंने कहा कि यही भावना के साथ अब पंचायत विभाग को तलाटीयों की पगार को लेकर विसंगतता को दुर करने का फैसला किया गया है। पंचायत और महेसुल के तलाटीयों को अब एकसमान स्तर पर बढ़ती और उच्च पगार स्तर के लाभ मिलेंगे। नीतिन पटेल ने कहा कि १२ हजार से अधिक पंचायत तलाटीयों के हितो को ध्यान में लेते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत और महेसुल के तलाटी को एकसमान न्याय मिले इस दिशा में पहल की गई है। पंचायत तलाटी महामंडल की मांग को ध्यान में लिया गया है। इससे पहले के परिपत्र को रद्द करने का फैसला भी किया गया है। जिसके चलते अब सालो से नौकरी कर रहे तलाटीयों में रही हुई पगार को लेकर विसंगतता दुर होगी। नीतिन पटेल ने बताया कि पहले तलाटी महामंडल की हडताल के समय महेसुल मंत्री कौशिकभाई पटेल, आदिजाति विकास मंत्री गणपतभाई वसावा, सामाजिक न्याय मंत्री इश्वरभाई परमार समेत के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री रुपाणी के साथ चर्चा विचारणा की थी और तलाटीयों के प्रश्न का हल लाने की बात की थी। आज राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई । जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है ।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)